SHRI K.N. BALAGOPAL: I would like to know whether the Government is requested by the corporates for tax exemption on CSR spending. If so, what is the logic behind that tax exemption? What is the Government's stand on the request?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, it was specified a minute ago and I would certainly be glad to repeat it that there are no tax exemptions provided for CSR. However, there are 11 specific activities which are mentioned in Schedule VII of the Act, and on those if they are spending under various provisions of Income Tax Act, there are exemptions given. But those are specified 11 activities which are very clearly laid out. It is only for those that there are exemptions. There are no special or additional requests from the companies to us about giving more exemptions.

ASHA karmi workers

*486. SHRI BHUPINDER SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the total number of ASHA karmi workers in the country;

(b) whether they have been given or will be given all the benefits like those to Government employees; and

(c) if so, the details of their service conditions?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Currently, there are 8.95 Lakh Accredited Social Health Activists (ASHAs) selected under the National Rural Health Mission (NRHM).

(b) Under NRHM, ASHAs are given performance based incentives in line with their role as honorary volunteers. There is no proposal to give them benefits like Government employees.

(c) Does not arise in view of (b) above.

MR. CHAIRMAN: Question No. 486. ...*(Interruptions)*... Mr. Rajeeve, please sit down. ...*(Interruptions)*... Please don't shout like this. ...*(Interruptions)*... There is a system by which names are taken up. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, minimum awareness in life does not require any educational qualification. सभापति महोदय, जो आशाकर्मी हैं, ये सारे देश में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। मंत्री जी ने इनके लिए यह नॉर्म बताया है कि 1000 की पॉपुलेशन वाले गाँव

में आशाकर्मी दिए जाएँगे। सर, हमारे ओडिशा में 53,341 विलेजेज़ हैं तथा पहाड़ी इलाकों में 50 एवं 25 की पॉपुलेशन के भी कई विलेजेज़ हैं, वहाँ पर आज आशाकर्मी की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, इसके लिए 8वीं-10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन होने की जो बात कही गई है, इस नार्म को वहाँ पर लागू न करके, जिस राज्य या गाँव में 100 परसेंट या 80 परसेंट से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी इस नार्म को रिलैक्स करने पर क्या सरकार विचार कर रही है?

डा. हर्ष वर्धन: सर, माननीय सदस्य ने दो बातें पूछी हैं। इसके लिए नॉर्मली यह क्राइटीरिया है कि 1000 की आबादी पर एक आशा वॉलंटियर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे दूर-दराज के इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में या जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इनके इलाके में अगर छोटे-छोटे आइसोलेटेड हैमलेट्स भी हैं और अगर वे 200-300-400 की आबादी के भी हैं तो वहाँ पर भी आशा वर्कर्स का सेलेक्शन किया जा सकता है। जब इलेवंथ फाइव इयर प्लान में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आशा की स्कीम शुरू हई थी तो इसके लिए आठवीं क्लास का क्राइटीरिया रखा गया था, लेकिन जब 2012 में पार्लियामेंट की स्टैंडिग कमिटी में इस बारे में विचार हुआ तो स्टैंडिग कमिटी ने ही यह डायरेक्शन दिया कि जहाँ-जहाँ दसवीं कक्षा पास महिलाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ अगर हम उनको प्रेफरेंस दे सकें तो दिया जाए। इसके बावजूद, हमें यह कहना है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बात की फ्रीडम दी गई है कि अगर उनको आठवीं कक्षा पास महिला भी नहीं मिलती है, तो जरूरत के हिसाब से वहाँ की पंचायत, वहाँ की आगनवाड़ी की टीम और वहाँ की कम्युनिटी के लोग मिलकर एज के रिलैक्सेशन के बारे में तथा एजुकेशन के रिलैक्सेशन के बारे में वहाँ के अनुसार फैसला कर सकते हैं।

श्री भूपिंदर सिंह: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब तक चलेगा? मेरे ख्याल में यह सारे देश और संसद की राय है कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे कभी भी बन्द न करे।

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI BHUPINDER SINGH: The question is that this should contine, especially in the tribal areas, in the undeveloped areas. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is a suggestion, not question. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPINDER SINGH: Yes, Sir, this is my suggestion that this should continue. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you. You have made your suggestion. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, my question is this. क्या गवर्नमेंट इसको बन्द करने के लिए सोच रही है? सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि...

Mr. Chairman: Only one question please. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपिंदर सिंह: सर, यह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वे आए दिन देश में आन्दोलन कर रहे हैं और हर असेम्बली का घेराव कर रहे हैं, क्या इसके बारे में सरकार को जानकारी है? अगर इसकी जानकारी है, तो क्या आप उनका रिम्यूनरेशन बढ़ाकर रेगुलर वर्कर्स के रूप में उनको मर्यादा देंगे?

Mr. Chairman: Please answer one of the questions posed.

डा. हर्ष वर्धन: सर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इलेवंथ फाइव ईयर प्लान में शुरू हुआ था। यह ट्वेल्फ्थ फाइव ईयर प्लान तक तो वैसे ही कटीन्यू होना है और सरकार के मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसको बन्द करने के बारे में हम सोचें। इसको और मजबूत करना, इसको और स्ट्रेंथन करना, फीडबैक लेकर इसके अंदर और प्रोफेशनल इनपुट्स डालना, इन सब के ऊपर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, मैं समझता हूँ कि इससे जुड़े प्रश्न के उत्तर में मैंने सारे कन्सर्न्स को ऐंड्रेस किया है।

श्रीमती विपल्व ठाकुर: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि आशा वर्कर्स जो केस लेकर जाती हैं, उन केसेज के मुताबिक इनको पैसा दिया जाता है। क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि वह पैसा भी इन लोगों को टाइम से नहीं मिलता है। क्या इसके लिए वे इंस्ट्रक्शन देंगे या क्या प्रोसीजर है, जिससे वह पैसा उसी समय उनको मिल सके। इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाएंगे, यह मैं जानना चाहती हूं?

डा. हर्ष वर्धन: अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रेगुलरली समयबद्ध तरीके से उनको ऑनरेरियम उपलब्ध हो, इसके लिए बैंक के अंदर खाता वगैरह खोलकर और अति शीघ्र आंगनवाड़ी वर्कर्स और पंचायत के माध्यम से उनके जो भी ऑनरेरियम/रिम्यूनिरेशन बनता है, जल्दी से जल्दी उनको देने की व्यवस्था है। इसके बारे में जब हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम-इम्प्लीमेंटेशन प्लान की मॉनिटरिंग करते हैं तो उस समय भी हम इस बात की चिंता करते हैं। आने वाले समय में यदि आपको या किसी भी मेंबर को किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में ऐसी शिकायत है तो हमारी जानकारी में लाएं, हम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से उसके बारे में बातचीत करेंगे।

श्रीमती झरना दास बैद्य: सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो आशा वर्कर्स हैं, वे पिछले पांच वर्षों से डिमांड करती रही हैं कि उनको मिनिमम वेज मिले। उनको मिनिमम वेज पांच सौ रुपये देने के लिए पिछली सरकार के हैल्थ मिनिस्टर से हमारी बात भी हुई थी, लेकिन वह उनको आज तक नहीं मिला है। आशा वर्कर एक सोशल वर्कर है। सर, हम भी तो वालंटियरी वर्कर हैं। हमें क्यों इतना ऑनरेरियम मिलता है, इतनी वेज मिलती है। उनको पांच सौ रुपये भी नहीं मिलते, जबकि ये लोग 24 घंटे काम करती हैं। तो इनको क्यों नहीं मिनिमम वेज मिलती है? इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, यह मैं जानना चाहती हूं।

डा. हर्ष वर्धन: महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनका जो ऐवरेज ऑनरेरियम है, वह आठ सौ रुपए से तीन हजार रुपए के बीच में है, डिपेंडिग अपॉन जो यह काम करती हैं। सर, दूसरा, जो कहा कि ये 24 घंटे काम करती हैं, वे 24 घंटे नहीं, उनका जो काम करने का समय है वह तीन घंटे से

मैक्सिमम पांच घंटे के बीच में है। उनको बहुत सेलेक्टेड काम करने की आवश्यकता होती है और इसके अलावा नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत वालंटियर के रूप में उन्हें एनरॉल किया गया स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी वे भारत सरकार के द्वारा दी गई राशि के साथ-साथ अपनी स्कीम्स से इनको समय-समय पर इंसेटिव देकर स्ट्रेंथन करते हैं।

श्री आनंद भास्कर रापोलू: सभापति महोदय, आज आशा वर्कर्स के ऊपर चर्चा से पूरे भारतवर्ष में आशा वर्कर्स का हौसला बढ़ा है, उसके लिए बधाई। ऑनरेबल चेयरमैन, Like the rural India is having revenue network, *Panchayati Raj* rural development network, the accredited social health activists' network and micro-finance network, the accredited social health activists' network is the health network. Have the Union Health Ministry studied the deficienciesofthehealthnetworkandtheuncoveredareas?Arethereanyplanstouplift them from the volunteer status to the activist status along with the required emoluments? This is my question.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, as far as the deprived areas in terms of health services are concerned, we have already, in fact, located 184 districts in the country where we are giving additional support to the State Governments to help them in various facets of the whole programme. As far as these ASHA workers are concerned, I have elaborated in detail that they are being strengthened and motivated. In fact, they are being imparted all sorts of training. Their credentials are being recognized. They are being considered for ANMs, GNMs and we are giving everything possible to encourage their good work.

बाजार से सिक्कों का प्रचलन से बाहर होना

*487. **श्री परवेज़ हाशमी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज र्व बैंक ने एक रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया है;

(ख) क्या ये मुद्रा बाजार में बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन में हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे एक, दो और पांच रुपए के सिक्के बाजार से गायब हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार ने 1990 के दौरान एक रुपए का नोट छापना बंद कर दिया था। ये नोट वैध मुद्रा के रूप में जारी हैं तथा इसलिए परिचालन में हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के अंकित मूल्य के सिक्के जारी करता है। पिछले 5 वर्षों में बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों द्वारा जारी किये गये सिक्कों का ब्यौरा निम्नलिखित है: